



भारत में निवेश न करने के फैसले से नुकसान में रहेगा टेस्ला : ओला कैब

नई दिल्ली ।

ओला कैब्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय बाजार में निवेश न करने का टेस्ला का फैसला अमेरिका की इस कंपनी के लिए एक बड़ा नुकसान है। भारत के लिए नहीं। एक्स पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि अगर यह सच है।

तो यह टेस्ला का नुकसान है, भारत का नहीं। हालांकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन और लिथियम का क्षेत्र अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब टेस्ला कुछ सालों बाद फिर से भारत को गंभीरता से देखेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला ने भारतीय अधिकारियों की पूछताछ का जवाब नहीं दिया है और अब उम्मीद नहीं है कि वह भारत में निवेश करेगी। यह खबर एलन मस्क के भारत दौरे को टालने के बाद आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला की आर्थिक

चुनौतियों के कारण कंपनी भारत में और निवेश की योजना नहीं बना रही है। टेस्ला की ग्लोबल सेल्स इस तिमाही में लगातार दूसरी बार कम हुई है और उसे चीन से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने नौकरियों में कटौती की घोषणा की है, अपने मुख्य साइबरट्रक स्टॉल को बेच दिया है और मेक्सिको में अपने प्लांट के निर्माण को टाल दिया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अब सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा

मोटर्स जैसी घरेलू कंपनियों पर ध्यान दे सकती है। अप्रैल में मस्क ने भारत की यात्रा रद्द कर दी थी, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे। बताया जा रहा है कि यह यात्रा कंपनी में जरूरी कामों के कारण रद्द हुई। इस साल मार्च में, भारत सरकार ने 41.5 अरब रुपये (500 मिलियन डॉलर) की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति में वैश्विक ईवी निवेश को आकर्षित करने और भारत को एडवांस ईवी के लिए एक बड़ा निर्माण केंद्र बनाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

माइक्रोसॉफ्ट ने की छंटनी, प्रभावित कर्मचारियों का खुलासा नहीं



वाशिंगटन । दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने इस सप्ताह एक और छंटनी की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार ये छंटनी कंपनी के विभिन्न टीमों और स्थानों को प्रभावित करेगी। हालाकि, माइक्रोसॉफ्ट ने इस ताजा छंटनी में प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट में लिंवडइन पर सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें संकेत मिलता है कि छंटनी का असर प्रोडक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट विभागों पर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने छंटनी की पुष्टि की। प्रवक्ता ने कहा कि हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए संगठन और कार्यबल में बदलाव जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने भविष्य के लिए और ग्राहकों एवं पार्टनर्स के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वित्तीय वर्ष 30 जून को समाप्त किया और इस दौरान पुनर्गठन प्रयास टेक दिग्गज के लिए असामान्य नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2023 में भी ऐसा ही किया था। ताजा छंटनी 2024 में पहले हुई कटौती के बाद हुई है। साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन में लगभग 2,000 नौकरियों में कटौती की थी। पिछले महीने, एक और छंटनी दौर में एंजुरे वलाडुड यूनिट और होलोलेस मिक्स्ड-रियलिटी टीम सहित लगभग 1,000 पदों पर असर पड़ा था। पिछले 18 महीनों में माइक्रोसॉफ्ट ने हजारों कर्मचारियों को निकाला है। ये छंटनी टेक इंडस्ट्री में चल रही व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा रही हैं। बताया जाता है कि अब तक लगभग 100,000 कर्मचारियों को टेक कंपनियों ने निकाला है। 2023 में टेक कंपनियां द्वारा निकाले गए कर्मचारियों की संख्या लगभग 260,000 थी।

भारत आएंगे फॉक्सकॉन के चेयरमैन रंग लियू



नई दिल्ली । ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन रंग लियू इस साल भारत का दौरान करने की योजना बना रहे हैं। लियू को चार जुलाई को ताइपे में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। भारत ताइपे एसोसिएशन के महानिदेशक मनहरसिंह यादव ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। लियू ने बयान में कहा कि मैं यह पुरस्कार पाकर अभिभूत हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे उन सभी महिलाओं तथा पुरुषों की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार करते हुए बेहद गर्व हो रहा है जो भारत में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इस वर्ष भारत में राष्ट्रपति से मिलने को उत्साहित हूं। वह पिछले साल जुलाई में सेमीकॉन इंडिया कॉन्वलेव में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। भारत में फॉक्सकॉन का कुल निवेश नौ से 10 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास होने का अनुमान है। कंपनी अपनी आईफोन उत्पादन सुविधा का विस्तार करने की प्रक्रिया में है। एचसीएल समूह के साथ संयुक्त उद्यम में एक चिप संयंत्र भी स्थापित कर रही है।

डीपीआइआईटी ने स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश की



नई दिल्ली । उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट आने से पहले स्टार्टअप कंपनियों से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की है। आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था जिसमें निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध स्टार्ट-अप की तरफ से जारी शेयरों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था भी शामिल है। उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। पहले एंजल कर केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट ने विदेशी निवेशक को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया था। टेस्ला के भारत आने से जुड़े सवाल पर सिंह ने कहा भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से ईवी के लिए जारी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

5 साल में पैदा हुई 8 करोड़ नौकरियां, श्रम मंत्रालय ने बताया कहां से आया इतना रोजगार



नई दिल्ली । ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और स्टार्टअप्स भारत में नौकरियां पैदा करने में प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। यह जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने दी है। उनका कहना है कि इन दोनों ने मिलकर पिछले पांच साल में करीब आठ करोड़ नई नौकरियां पैदा की हैं।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आमतौर पर दुनियाभर के संगठन बनाते हैं। इसका मकसद वैश्विक प्रतिभा, संसाधनों और विशेषज्ञता का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ये अमूमन बड़े कॉर्पोरेशन का हिस्सा होते हैं और कृष, आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

श्रम मंत्रालय की सचिव ने क्या कहा

श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा भारतीय ऑफ इंडिया (ईएफआई) के बोले रही थीं। उन्होंने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का हवाला देते हुए 5 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा होने की बात कही।

डावरा ने श्रम कानूनों को अपराधमुक्त करने और महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने जैसे सुधारों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने व्यापार को

आसान बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। डावरा ने कहा, %सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण जैसे सुधारों से भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, 29 श्रम कानूनों को चार श्रम कानूनों में संविताबद्ध किया गया है। एक राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल सक्रिय है और कौशल मंत्रालय से डेटा एकीकृत किया जा रहा है।

भारत में 1 करोड़ गिग वर्कर्स

डावरा ने कहा कि भारत में 1 करोड़ गिग वर्कर हैं और साल 2030 तक गिग इकोनॉमी से करीब 2.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। गिग वर्कर का मतलब ऐसे कर्मचारियों से हैं, जो स्थायी कर्मचारी नहीं होते। ये लोग फ्रीलान्सर या फिर काफी कम समय के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। जैसे कि जोमेटो या स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म के डिलिवरी ब्रॉय और ओला-उबेर से जुड़े ड्राइवर।

गिग कर्मचारी अर्थव्यवस्था के सर्विस सेक्टर का अहम हिस्सा होते हैं। यह क्षेत्र लगातार तेजी से बढ़ रहा है। डावरा ने कहा कि सरकार ने नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि एआई पर हमें किसी नतीजे पर पहुंचने से और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है।

बैजूस के पूर्व कर्मचारी भी बकाये वेतन को लेकर एनसीएलटी पहुंचे

नई दिल्ली ।

नकदी संकट से जूझ रही एडटेक फर्म बैजूस के 62 पूर्व कर्मचारियों ने अपने बकाये वेतन भुगतान नहीं करने पर कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के बेंगलूर पीठ में दिवालिया कार्यवाही का मामला दायर करने के लिए नोटिस भेजा है। बैजूस ट्यूशन सेंटर दिल्ली के पूर्व गणित शिक्षक और पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने कहा कि बेंगलूर की कानूनी फर्म कैनवास लीगल ने 62 कर्मचारियों की ओर से 2.30 करोड़ रुपये से अधिक का डिमांड नोटिस भेजा है। डिमांड नोटिस में कर्मचारियों को पिछले साल से बकाया वेतन तुरंत देने की मांग की गई है। कंपनी द्वारा 4 जुलाई को भेजे गए पत्र में कहा गया है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पत्र मिलने के 10 दिनों के भीतर बकाया परिचालन ऋण को बगैर किसी शर्त के पूरा चुकाएं और ऐसा नहीं करने पर हम थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड

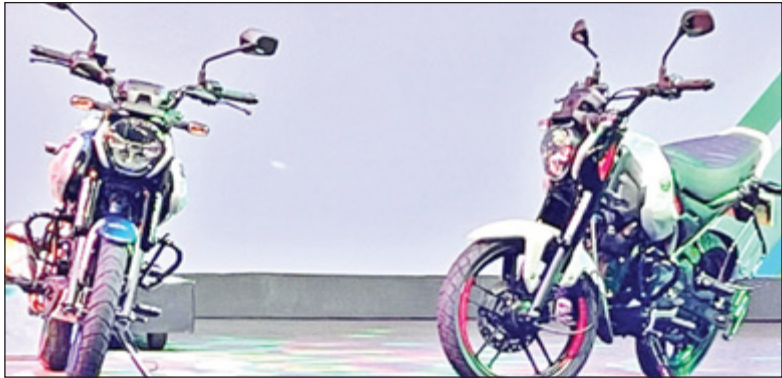


(बैजूस की मूल कंपनी) के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता समाधान के तहत कार्यवाही शुरू करेंगे। बैजूस के 1,500 से अधिक नाराज पूर्व कर्मचारी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो गए हैं। उनमें से अधिकतर कर्मचारी अपने बकाया राशि के भुगतान के लिए कंपनी को एनसीएलटी के बेंगलूर पीठ ले जाने की प्रक्रिया में हैं। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने हाल में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें लाड ने भी पुराने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के लिए कहा था।

बजाज ने उतारी दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125, साथ ही पेट्रोल से भी चलेगी

नई दिल्ली ।

बजाज ऑटो ने 25 साल पहले जब देश में सीएनजी से चलने वाला पहला तिपहिया उतारा था, उस समय कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिल्ली की उनकी टीम ने फोन कहा कि ऑटो चालकों के एक जत्थे ने दिल्ली में कंपनी के शोरूमों के कांच तोड़ दिए हैं। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 को उतारते हुए बजाज के जेहन में उसकी याद ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे लगा था कि सीएनजी तिपहिया चालकों के लिए बेजोड़ होगा। मगर चालक इसलिए नाराज थे क्योंकि दिल्ली में उस समय केवल एक सीएनजी पंप था और ऑटो में गैस भरवाने के लिए उन्हें 10-12 घंटे तक कतार में खड़े रहना पड़ता था। इस वजह से उन्हें सीएनजी के कारण होने वाली बचत का फायदा नहीं मिल रहा था। मगर अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। अब भारत के 335 शहरों में 6,000 सीएनजी पंप हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी के अनुसार फ्रीडम 125 तीन वैरिएंट और 7 रंगों में उपलब्ध



होगी। इसकी कीमत 95,000 से 1.1 लाख रुपये के बीच होगी। फ्रीडम 125 को उद्योग की तस्वीर बदलने वाली बाइक बताते हुए बजाज ने कहा कि इस बाइक से पेट्रोल आयात, हानिकारक उत्सर्जन, पेट्रोल की ऊंची कीमतों और चालिंग स्टेशन खोजने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। अपने 34 साल के

सफर में 100वां उत्पाद उतारते हुए बजाज ने कहा कि आज मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है। फ्रीडम 125 सीएनजी के साथ ही पेट्रोल से भी चलेगी। बाइक चलाते समय केवल एक स्विच दबाकर पेट्रोल से सीएनजी पर जा सकते हैं या सीएनजी से पेट्रोल पर आ सकते हैं।

मिडिलक्लास का सपना हो रहा साकार, 30 मझोले शहरों में आवासीय बिक्री 11 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। आवासीय मांग में वृद्धि केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 30 मझोले शहरों में भी आवासीय सपनियों की बिक्री 11 प्रतिशत



बढ़कर करीब 2.08 लाख इकाई हो गई। रियल एस्टेट डेटा विश्लेषक कंपनी प्राप्रइक्रीटी ने मझोले शहरों के आवासीय बाजार पर एक रिपोर्ट जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में आवासीय बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 2,07,896 इकाई हो गई, जबकि 2022-23 में यह 1,86,951 इकाई थी। अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत, नासिक, गांधीनगर, जयपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और मोहाली का इन 30 मझोले शहरों की कुल बिक्री में 80 प्रतिशत का योगदान रहता है। इन 10 शहरों में 2023-24 में कुल 1,68,998 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई, जो 2022-23 में 1,51,706 इकाई की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। अन्य मझोले शहर भोपाल, लखनऊ, गोवा, कोयंबटूर, रायपुर, विजयवाड़ा, इंदौर, कोच्ची, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर, गुटूर, भिवाड़ी, देहरादून, लुधियाना, चंडीगढ़, आगरा, मेसूर, सोनीपत, पानीपत और अमृतसर हैं। संपत्ति की कम कीमतों और वृद्धि की संभावनाओं के दम पर मझोले शहरों ने बड़े शहरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। किफायती आवास के कारण इन शहरों में बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए अपना मकान खरीदने का सपना साकार हो रहा है।